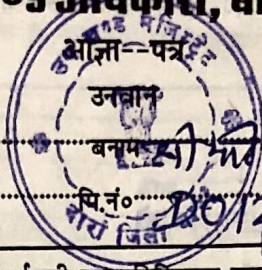


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाराँ जिला-बाराँ

14/11/11

22/1/11



सुकदमा 136 CRN
 राम चरण कौं
 बनावसी नि
 पिन नं० 20/12/11

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज नम्बर व ता० अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

10/8/11

रिपोर्ट खीटा टिप्टी जर्म, उपखण्ड
 जर्म टिकिच किच जर्म जर्मनी से तारीख
 से कीमिच काली 18/10/11 फिट को

18/10/11/37
 29/11 24/5/11
 13/12 19/11
 10/12
 3/1/12 21/1/11
 25/12
 10/11/12 25/3
 29/11/12 29/3
 7/2/12
 29/2 29/4
 27/3 1/6
 24/4 8/5
 22/5 5/8/11
 3/7 2/9/11
 7/8 21/10/11
 29/8/12 27/11/11

18/10/11. गणतंत्रिय अधिकारी के हुक्म को
 में रहने से पूर्वगत दिनांक 29/11/11
 प्रस्तुत हो।

29/11/11. गणतंत्रिय अधिकारी के हुक्म को
 में रहने से पूर्वगत दिनांक 30/11/11
 प्रस्तुत हो।

13/12/11

करीब उपखण्ड का इन्फार्मेशन। एड 3 का तारीख
 उनके रिपोर्ट एड परीच रॉबर्ट से जर्म
 इन्फार्मेशन एड 4 की तारीख 6 का इन्फार्मेशन 6 का
 इन्फार्मेशन के वक्त किच हुक्म नवम्बर इन्फार्मेशन
 उपखण्ड के प्रिन्सिपल जर्म। इन्फार्मेशन 5 का
 इन्फार्मेशन 6 का इन्फार्मेशन 7 का इन्फार्मेशन
 जर्म। इन्फार्मेशन 8 का इन्फार्मेशन 9 का इन्फार्मेशन

18/9/12
 9/10/11
 30/10/12
 20/11/11
 4/12/12
 18/12
 8/1/13
 11/2
 5/3
 2/4
 9/4/11
 30/4
 7/5
 2/5
 29/5
 27/5/11

31/1/12. गणतंत्रिय अधिकारी के हुक्म को
 में रहने से पूर्वगत दिनांक 31/1/12 को
 प्रस्तुत हो।

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां


उनवान

रामरतन वगे0 बनाम श्रीमति मोहनी वगे0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या D012/11

दायरा तिथि :- 18.08.2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। रकबा - कमी पूर्ति के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा।</p> <p>निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बनवारी लाल बैरवा) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बारां</p>	